पंचदश

बिहार विधान-सभा

तृतीय सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि — 30 श्रावण, 1933 (श०) / 21 जुलाई, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—11

(1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	02
(2) कृषि विभाग	..	05
(3) नगर विकास एवं आवास विभाग	..	03
(4) ग्राम एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	01
कुल योग	..	11

कार्रवाई करना

10. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "नहीं हुआ राशि का शत-प्रतिशत उपयोग" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010-11 में राज्य योजना से पावर टीलर अनुदान मद में 39.92 करोड़ समेकित सिथियल विकास कार्यक्रम में 12.17 करोड़ समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम योजना मद में 33.19762 लाख एवं कृषि यांत्रिकीकरण योजना मद में 32.29 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, पर पदाधिकारियों की शिथिलता के चलते उपर्युक्त योजनाओं में क्रमशः 7.76 करोड़, 3.26 करोड़, 32.92 करोड़ एवं 2.57 करोड़ रुपया सरेन्डर करना पड़ा;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

11. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को पटना से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के शीर्षक "लापरवाही से 29 करोड़ वापस" की ओर ध्यान देते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम में 38 नये जलापूर्त्ति केन्द्र निर्माण हेतु विभाग द्वारा 29 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर विवाद के कारण आवंटित 29 करोड़ रुपये वापस ले लिये गये;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना को असफल करवाने वाले दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बजट बनाना

12. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में छः माह पूर्व कृषि कैबिनेट का गठन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि का अलग से बजट बनाने हेतु अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि देश के दूसरे राज्यों यथा छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक में कृषि के लिए अलग से बजट बनाने की व्यवस्था की गई है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में कृषि के विकास हेतु अलग से कृषि बजट बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि वापस करना

13. श्री संजय सिंह "टाईगर"--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 1996 से 1999 के बीच बिहार राज्य के किसानों को खाद आपूर्ति किये बिना देश के 22 खाद कम्पनियों को अनुदान की राशि साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का राज्य सरकार द्वारा भुगतान वर्ष 1999 में कर दिया गया है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर कम्पनियों से अनुदान की राशि वापस करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

बंद करना

14. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 16 मई, 2011 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''हर जगह सड़कों पर मौत के कुएं'' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना की सड़कों पर 6 हजार से ज्यादा मेनहोल एवं 7 हजार से ज्यादा कैचपीट वर्षों से खुले हैं, जिससे हर वर्ष कई लोगों की जान जा रही है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त मेनहोल और कैचपिट को बन्द करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पानी की व्यवस्था

15. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 7 मई, 2011 के अंक में छपी खबर ''रसातल में पानी'' के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, नालंदा, जमूई, मुंगेर, गया, शेखपुरा सहित 21 जिलों के 45 प्रखंडों में चापाकलों में पानी नहीं आने से जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी लगभग 1 लाख चापाकल खराब है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब चापाकलों को ठीक कराकर उपरोक्त प्रखंडों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रारंभ करना

16. श्री अवनीश कुमार सिंह--दिनांक 11 जुलाई, 2011 को प्रकाशित समाचार शीर्षक '' सौ साल में भी झुग्गीमुक्त नहीं होगा देश'' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देश के शहरी झुग्गी बस्तियों में रहनेवाले गरीबों को सस्ती दर पर होमलोन के माध्यम से घर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा दिसम्बर 2008 में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर देश के सभी राज्यों को इसकी सूचना दी गयी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना को लागू हुए ढाई वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद राज्य में उपरोक्त योजना आजतक प्रारम्भ ही नहीं की गयी, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार इसे कबतक प्रारंभ करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

17. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 39956 बस्तियों में से 35233 बस्तियों एवं वर्ष 2009-10 में 40508 बस्तियों में से मात्र 27103 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करायी गयी है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लक्ष्य के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, अगर हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

18. डॉ० इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 25 अप्रील, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''बुकिंग के बाद भी कब मिलेगी गैस, पता नहीं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला सहित राज्य के सभी 37 जिलों में रसोई गैस का नम्बर लगाये जाने के 15-20 दिन के बाद भी गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है तथा बाजार में गैस की कालाबाजारी छोटे सिलेण्डरों को भरने एवं होटलों व रेस्तरों में घरेलू सिलेण्डरों में कोई कमी नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में गैस सिलेण्डर को उपभोक्ता को सुचारू ढंग से मुहैया कराने के लिए संबंधित अधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

राशि खर्च करना

19. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राष्ट्रीय बॉस मिशन वित्तीय वर्ष 2006-07 में शुरू की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि यह योजना शत्-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि केन्द्र से इस मद में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक 651.87 लाख रुपया प्राप्त हुआ है, जबकि व्यय मात्र 459.35 लाख रुपया ही हुआ है;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बाकी बचे 192.52 लाख रुपये को कबतक खर्च करने का विचार रखती है ?

निर्माण करना

20. श्री सुबोध राय--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''अधूरा है ई-किसान भवन का सपना'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने हर प्रखंड में किसानों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-किसान भवन बनाने का फैसला लिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि पहले चरण में 166 प्रखंडों में भवन की स्वीकृति मिली थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 332 हो गई और पिछले साल ही पूरा करना था, लेकिन अधूरा है;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने सबके लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जिन प्रखंडों के लिए स्वीकृति दो वर्ष पहले दी गई थी, वहां अबतक किसानों को यह सुविधा नहीं मिली है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अधूरे ई-किसान भवन का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 21 जुलाई, 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 29--डी०टी०पी०--450--